RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-03
March -2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

भारत में लोकनीति निर्माण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण–मूल्यांकन

डॉ आशुतोष मीना

असिस्टेंट प्रोफेसर (लोक प्रशासन) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आबूरोड

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 16 Mar 2020

Keywords
भारतीय संविधान, भुखमरी, गरीबी

ABSTRACT

भारतीय संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख होने के बावजूद आमजन, शिक्षित वर्ग, शिक्षाविद्, लोकसेवक, विद्यार्थियों और राजनेताओं के चिन्तन व सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भाव संतोष जनक नहीं कहा जा सकता। आर्थिक–सामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन, आधारभूत संरचना निर्माण, औद्योगिक विकास इत्यादि के लिए सरकार नीतियाँ बनाती है, इन नीतियों के आधार पर ही निर्णय व योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। देश को स्वतंत्र हुए सात दशक बीत चुके और 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' को संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में शामिल हुए भी 45 वर्ष हो चुके हैं। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ को पार कर चुकी है। भारत मानव श्रम के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद प्राद्योगिकी व तकनीक के क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि विदेशी तकनीक पर निर्भर है। आज भी देश का बडा हिस्सा भुखमरी, गरीबी, अभाव व अन्याय से ग्रसित है। मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि भारत में समस्याओं को समझने व समाधान के लिए वैज्ञानिक व तार्किक प्रयास नहीं किए जाते। सरकार द्वारा भी नितियाँ बनाते समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा व आम जनमानस की परंपरागत मान्यताओं को ध्यान में रखा जाता है। इस आलेख में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नीति–निर्माण में आवश्यकता व महत्व का विश्लेषण किया गया है

परिचय–

42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे देश के संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल किया है, अनुच्छेद 51A(h) जोड़ा गया इसमें कहा गया "प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच व सुधार की भावना का विकास करे"।[1] भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया' में 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' शब्द का जिक्र किया।[2] उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एसी मनोवृति के रूप में परिभाषित किया जिसमें नए साक्ष्य के प्रकाश में किसी की धारणा को बदलने की क्षमता है और बिना प्रमाण व परीक्षण के कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता।

हमारे राष्ट्र ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार के प्रयास किए हैं और इसके महत्व पर जोर दिया है। सरकार द्वारा साइंटिफिक पॉलिसी रिजॉल्यूशन 1958, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी द्वारा निर्मित विज्ञान की पहली नीति थी जिसने विज्ञान के लगभग हर क्षेत्र में अनुसंधान पर बल दिया। साइंस, टेक्नॉलॉजी एंड इन्नोवेशन पॉलिसी 2013 में वैज्ञानिक शोध के साथ समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास पर भी बल दिया गया।[3] यद्यपि हमारी सरकार ने हमेशा भारतीय नागरिकों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है फिर भी देश के सामाजिक–आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत संकल्प, प्रस्तावों व योजनाओं को विकसित करते हुए इस दृष्टिकोण को ठीक से विकसित करने के लिए अभी बहुत कठिन और लंबा रास्ता तय करना है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ–

वैज्ञानिक दृष्टिकोण में समस्याओं के समाधान को समझने के लिए एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक मनोवृति शामिल है। इसे मन की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति निर्णय लेता है और तर्कसंगत विश्वास के अनुसार कार्य करता है जिसे प्रयोग व परीक्षण के माध्यम से वैध किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा को केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण व आम जन से बहुत दूर माना जाता है। प्राचीन काल में सुकरात, बुद्ध से लेकर आधुनिक समय में राजा राम मोहन राय व पेरियार के नेतृत्व वाले तर्कवादी आंदोलन एवं विभन्न समाज सुधारकों ने सामाजिक परिवर्तन, समाज व राष्ट्र के आर्थिक–सामाजिक विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की है।

डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक 'टर्निंग पॉइंट्स' में विकासात्मक राजनीति शब्द से परिचय कराया, इसकी शर्त यह है कि राजनीति के आधार रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया जाए।[4] इस पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है कि इस तरह के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले सभी वैज्ञानिक समाज के खिलाफ नहीं हैं। वे केवल उन मान्यताओं को मान्य करने और परीक्षण करने का एक नया तरीका पेश करना चाहते हैं जो समाज में बहुत लंबे समय से बिना किसी वैज्ञानिक आधार के प्रचलित हैं। वे सभी समाज जो दृढ़ता से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी के विकास में विश्वास करते हैं, वे दीर्घ अवधि के लिए समृद्ध रहेंगे। हमारे देश में अभी भी किसी भी प्रकार के नियोजन या नीति के विकास में वैज्ञानिक सिद्धांतों व वैज्ञानिक मनोवृति के प्रयोग का अभाव है। यदि हमारे देश के संसाधनों से वंचित लोगों को बेहतर

RRIJM 2015, All Rights Reserved

जीवन प्रदान करने की आवश्यकता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपरिहार्य है।

लोक नीति निमार्ण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भूमिका–

हम जिस समाज में रहते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे समुदाय में लोगों में अभी भी वैज्ञानिक सोच की गहरी समझ का अभाव है। सरकार ने पहले ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मौलिक कर्तव्य बनाकर इसे नागरिकों के दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास किया है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग पुरानी मान्यताओं से बंधे हुए हैं और अभी भी इनका आँख मूँद कर अनुसरण करते हैं और यह सवाल नहीं करते कि समाज में इस तरह की प्रथा क्यों है ?, इसका समाज को क्या लाभ है ? और ना ही यह प्रश्न करते हैं कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या नहीं ? हमारी सरकार अधिक से अधिक वैज्ञानिक निर्णय लेने और ऐसी नीतियां बनाने का प्रयास कर रही है जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अवधारणा पर आधारित हों। हालांकि सरकार के लिए लोगों की भ्रामक सूचनाओं, जड़ व रूढ़िवादी सोच में बदलाव लाना मुश्किल व चुनौतीपूर्ण कार्य है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोणः नीति निर्माण और नियोजन–

आधुनिक समय में सरकार और उन सभी लोगों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है जो हमारे देश की बेहतर योजना और विकास के लिए सार्वजनिक नीतियाँ बनाने में शामिल हैं। नियोजन में संसाधनों का आवंटन इस तरह से होता है कि यह हमारे देश के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो और नागरिकों के लिए लाभकारी हो। इस देश के सामाजिक–आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एवं नीतियाँ व योजना बनाने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लागू करना अनिवार्य हो गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा को वैज्ञानिक नियोजन में शामिल करने से पहले समाज और इसके लोगों में इसकी समझ विकसित करना आवश्यक है।

हमारे राष्ट्र की उपलब्धि एवं पिछले वर्षों में आई सभी कठिनाईयों और कमियों के मूल्यांकन के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण नीति निर्माण और नियोजन का हिस्सा बन सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से नीति का कार्यान्वयन इस प्रकार होना चाहिए कि यह नागरिकों की लोकप्रिय मान्यताओं का भी सम्मान हो सके और साथ ही हमारे समाज में मूल्ययुक्त परिवर्तन करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके, इसी से विकास का मार्ग प्रशस्त हा सकता है। अपने देश के विकास के लिए नागरिकों को अपने परंपरागत रूढ़िवादी विश्वासों व मान्यताओं को बदलने और सरकार के साथ–साथ न्यायपालिका के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। यह शिक्षित लोगों की जिम्मेदारी है कि वे उन निर्णयों और नीतियों का समर्थन करें जिन्हें वैज्ञानिक नियोजन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। हालाँकि अधिकांश पढ़े–लिखे लोग कम शिक्षित लोगों की तुलना में अधिक अन्धविश्वासी व रूढ़िवादी सोच रखते हैं जो उनके मन–मस्तिष्क में गहराई तक घर की हुई है।

कांतारू राजीवरू बनाम भारत युवा वकील संघ[5] मामले में एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें सभी महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता अपनी संस्कृति की सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे रहा था, जहां 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को उस मंदिर में प्रवेश करने और प्रार्थना करने की अनुमति नहीं थी। उसने सर्वोच्च न्यायालय से एक निर्णय पारित करने की अपील की जहाँ महिलाओं को अपने धर्म का पालन करने के अपने अधिकार का पालन करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। जिस समय मामला दायर किया गया था उसी समय केरल में बाढ़ के बाद भारी वर्षा देखी गई थी। उसी दिन, आरबीआई बोर्ड के नवनियुक्त सदस्य एस गुरूमूर्ति ने ट्वीट किया था कि महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है, इससे भगवान अयप्पा क्रोधित हो गए और भगवान ने राज्य में बाढ़ ला दी।[6]

सरकार के कुछ निर्णयों व योजनाओं का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए तो नीति निर्माताओं की वैज्ञानिक सोच का पता लग सकता है। 29 जून 2017 को उत्तरप्रदेश सरकार ने तीर्थ यात्रियों के मार्ग में आने वाले 'गूलर' के पेड़ों को कटवाने के आदेश इस आधार पर जारी किए क्योंकि 'गूलर' का पेड अपवित्र होता है।[7] वैज्ञानिक विश्लेषण से स्पष्ट है कि गूलर के पेड़ एक औषधीय वृक्ष है, छायादार है और बहुत लाभदायक है।

इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (ICHR) द्वारा मार्च 2017 में निर्णय लिया कि एक परियोजना अक्टूबर–नवम्बर 2017 में शुरू की जाएगी जिसका उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि रामसेतु का निर्माण प्राकृतिक है, मानव निर्मित है या वानर निर्मित पुल है। वैज्ञानिक समुदाय, इतिहासकार, पुरातात्विक विशेषज्ञ और जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इसे अवैज्ञानिक बताया, तीव्र प्रतिक्रिया दी लेकिन परियोजना जारी रही।[8] 5 मार्च 2018 को आईसीएचआर चेयरमेन का पद ग्रहण करने के बाद अरविंद जामखेडकर ने कहा "भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद के सदस्य एसी परियोजना के विरूद्ध हैं, वे इसे लेकर बहुत क्रोधित हैं। हम इस तरह का कोई अध्ययन व खर्च नही करेंगे"।[9] अंत में यह परियोजना वापस लेनी पड़ी।

पौराणिक सरस्वदी नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास, इसके लिए सरस्वती हेरिटेज प्रोजेक्ट बनाया गया, प्रस्ताव के समय इसकी अनुमानित लागत 108.70 करोड़ थी। ओएनजीसी सरस्वती नदी के प्रवाह पथ पर 100 कुओं का विकास करेगा। पर्यावरणविदों और जल विशेषज्ञों का कहना है कि पौराणिक नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास अवैज्ञानिक हैं और कहा कि सरकार को यमुना जैसी नदियों को पुनर्जीवित करने में ऊर्जा व धन लगाना चाहिए जो प्रदूषण की मार झेल रहीं हैं। वाटरमेन के नाम से विख्यात राजेन्द्र सिंह के अनुसार "जिस प्रकार सरकार सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करना चाहती है उससे यमुना को नुकसान होगा, भूजल खोदने से नदियों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता"।[10]

RRIJM 2015, All Rights Reserved

जुलाई 2016 में उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और हौम्योपैथी विभाग ने 'संजीवनी बूटी' की खोज के लिए एक समिति का गठन किया कि हनुमानजी संजीवनी बूटी कहाँ से लाए। इसके लिए 25 करोड़ रू का बजट आवंटित किया गया।[11] इस प्रकार के निर्णय का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े आईआईटी खड़गपुर को वास्तुशास्त्र पर स्नातक पाठ्यक्रम में कोर्स शुरू करने को कहा गया। यह तर्क दिया गया कि वास्तुशास्त्र की शुरूआत ऋग्वेद में हुई और यह वैज्ञानिक है।[12] यह प्रयास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परे है।

इसी प्रकार 'काऊपेथी' और 'पंचगव्य' योजनाओं पर भी वैज्ञानिकों ने प्रश्नचिन्ह लगाया है कि यह धन, समय व ऊर्जा का अपव्यय है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता–

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भरता के बीच एक संबंध है। हमारा देश उपलब्ध प्रौद्योगिकी और औद्योगिक आधारभूत संरचना के साथ आत्मनिर्भर हो रहा है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् कुछ वास्तविक चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। राष्ट्र परमाणु और परमाणु ऊर्जा आदि के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है। हम देश की मौजूदा परिस्थितियों से भी अवगत हैं। दुनिया के शीर्ष दस उद्योगपति देशों में होने के बाद भी हम विकसित देशों के साथ महत्वपूर्ण मोलभाव या अनुबंध नहीं कर पाते हैं।

आत्मनिर्भरता का मतलब है किसी भी परियोजना के अनुसंधान और विकास में शामिल सभी वैज्ञानिक विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के मोलभाव व खरीद में शामिल होने चाहिए। मान लीजिए कि वे इस प्रकार की विस्तृत चर्चा में शामिल नहीं हैं, उस स्थिति में वे तकनीकी जानकारी, उपलब्धि के तरीकों और उन सभी क्षेत्रों से अवगत नहीं होंगे, जिनका प्रौद्योगिकी के चयन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फिर हम वैज्ञानिकों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे हमारी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार प्रौद्योगिकी को अपनाएँ और तदनुसार विशिष्ट नीतियों को लागू करें। आमतौर पर सरकार के सदस्य जो इस तरह की सार्वजनिक नीतियां बनाने में शामिल होते हैं उन्हें विदेशी कंपनियों के साथ इस तरह की बातचीत में शामिल होने की जिम्मेदारी दी जाती है।

यह आवश्यक नहीं है कि वे इस क्षेत्र में आवश्यक तकनीकी जानकार हों, वे ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जो हमारे देश की स्थिति के विषय में तकनीकी रूप से अनुकूल न हों। इसलिए जो वैज्ञानिक शुरू से ही किसी विशेष परियोजना के अनुसंधान और विकास में शामिल हैं, उन्हें तकनीकी जानकारी वाले किसी भी ऐसे समझौते में प्रवेश करते समय अधिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र में बेहतर नीतियों के कार्यान्वयन के लिए यह उन्हें नीति निर्माताओं की मदद करने में सक्षम करेगा।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षा–

हमारे देश में समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी अंधविश्वास और रूढिवादी, जड़वादी सोच के जाल में फंसा हुआ है। इसलिए नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शिक्षा देना अनिवार्य है। मुख्य रूप से बच्चों के पाठ्यक्रम और शिक्षण में इसे शामिल करना महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि बच्चों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए बचपन सबसे अच्छा समय है। इसलिए ऐसे विषयों को जोड़ना आवश्यक है जो बच्चों के वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ा सकें और उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास में उनकी मदद कर सकें।

शैक्षिक नीतियों का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण को और अधिक छात्र–अनुकूल बनाकर छात्रों की रचनात्मक क्षमता का विस्तार करना और छात्रों के व्यक्तित्व के समग्र विकास में मदद करना। यदि स्कूल में अच्छी प्रकार से तैयार पाठ्यक्रम आधारित गतिविधियाँ की जाती हैं तो यह वैज्ञानिक ढांचे या वैज्ञानिक परिधि में व्यावहारिक अवलोकन व अनुभव के माध्यम से अर्जित ज्ञान को आत्मसात करने में बच्चों की मदद करेगा; इस प्रकार बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए एक आधार तैयार किया जा सकता है।

लाभ–

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने व्यक्तियों को किसी भी नीति, योजना व मुद्दे पर जिम्मेदार व्यक्ति से या सरकार से प्रश्न करने की क्षमता और स्वतंत्रता प्रदान की है। इसके लिए एक उदाहरण शायरा बानो बनाम भारत संघ[13] का मामला हो सकता है, जहां याचिकाकर्ताओं ने लंबे समय से चली आ रही तीन तालक की प्रथा पर सवाल उठाया था।
- अकादमिक व शैक्षणिक पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल करने के बाद शिक्षण के तरीकों में निस्संदेह सुधार हुआ है। आजकल छात्रों की किसी भी तरह के अंधविश्वास में रूचि कम हो रही है, आज युवाओं में तार्किक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है लेकिन यह अभी शैशव काल में है। वे हर विचारधारा या परंपरा के पीछे वैज्ञानिक तर्क खोजने की कोशिश करने लगे हैं। ये छात्र हमारे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, यदि उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व का विकसित कर लिया, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इस देश का भविष्य महान हाथों में होगा।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास निश्चित रूप से हमारे समाज में प्रचलित जातिवाद की व्यवस्था सहित सामाजिक बुराइयों, महिलाओं, पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय को मिटाने में मदद करेगा।

हानि–

- अधिकांश नीति निर्धारक और राजनेता अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अपनी सार्वजनिक नीतियों में लोगों

RRIJM 2015, All Rights Reserved

की रूढ़िवादी अवैज्ञानिक विचारधाराओं और विश्वासों को शामिल करते हैं, और सरकार विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करने के बजाय लोकप्रियता पाने के लिए जनमत को महत्व देती है।

- भारतीय जनमानस अभी भी अवैज्ञानिक रूढ़िवादी विचारधारा से ग्रस्त है, लोग वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं का समाधान नहीं करते।
- आजादी के सत्तर साल बाद भी भारतीय वैज्ञानिक अल्प बजट पर काम कर रहे हैं, और उनके पास वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए अन्य देशों की तरह संसाधन नहीं हैं।

निष्कर्ष–

यद्यपि सरकार ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के साथ–साथ नागरिकों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन आजादी के सात दशक बाद अभी भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रदान किए गए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को पूरा करने में असफल रहे हैं। तैयार की गई सभी नीतियां उस सामाजिक परिवेश पर निर्भर करती हैं जिसमें हम रह रहे हैं। जो व्यक्ति नीतियां बना रहे हैं उनको भी योजना निर्माण में वैज्ञानिक तरीकों को शामिल करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती क्योंकि वे भी इस सामाजिक वातावरण के सदस्य हैं।

यहां तक कि उनकी सोच आसपास के लोगों की विचारधाराओं और मानसिकता से प्रभावित हो रही है। इसलिए ऐसी सार्वजनिक नीतियों को विकसित करने के लिए हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान है और उनके आसपास मौजूद लोकप्रिय विचारधाराओं की तुलना में अलग–अलग दृष्टिकोण हैं। सामाजिक–आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और समाज के विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित सार्वजनिक नीतियाँ बनाना आवश्यक है ताकि सभी व्यक्ति अपनी सोच व चिन्तन को व्यापक बना सकें और बेहतर जीवन जी सकें। यह जिम्मेदारी उन राजनेताओं व अधिकारियों के हाथ में है जो इस तरह की नीतियों को विकसित करने में शामिल हैं क्योंकि उचित प्राधिकरण और आदेश के बिना, रूढ़िवादी समाज में रहने वाले लोगों के लिए अपने अंधविश्वासों को बदलना मुश्किल होगा।

संदर्भ–

1 अनुच्छेद 51A(h), भारत का संविधान
2 नेहरू, जवाहरलाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया (1946), पृ.सं. 512
3 https://dst.gov.in/sites/default/files/STIP_2020_Background_Note.pdf
4 कलाम, डॉ अब्दुल, टर्निंग पाइंट्सः अ जर्नी थ्रू चेलेन्जेज, 2014
5 Review Petition (Civil) No. 3358 of 2018 in Writ Petition (Civil) No. 373 of 2006
6 https://www.firstpost.com/india/s-gurumurthy-mounts-detailed-defence-of-his-sabarimala- kerala-floods-tweet-rbi-role-and-right-to-speak-despite-abuse-5015511.html
7 Rashid Omer (2017), Does the UP govt. give a fig for this 'inauspicious' tree ? The Hindu, 30 June, Available at: https://www.thehindu.com/news/national/other-states/does-the-up-govt- give-a-fig-for-this-inauspicious-tree/article19189439.ece
8 Pathak Vikas (2017), ICHR to undertake pilot project on Ram Setu structures, The Hindu, 25 March, Available at: https://www.thehindu.com/news/national/ichr-to-undertake-pilot-project-on-ram-setu-structures/article17647603.ece
9 THE HINDU (2018) ICHR NOT TO STUDY NATURE OF 'RAM SETU' STRUCTURES, 8 APRIL, AVAILABLE AT: HTTPS://WWW.THEHINDU.COM/NEWS/NATIONAL/ICHR-NOT-TO-STUDY-NATURE-OF-RAM-SETU/ARTICLE23471382.ECE
10 Aggarwal Myank (2019), bringing back the Ancient Saraswati river, MONGBAY, 19 July, Available at: https://india.mongabay.com/2019/07/upcoming-elections-in-haryana-boost-efforts-to-revive-the-ancient-saraswati-river/
11 Abraham B (2016) Uttarakhand government allocates Rs 25 crore to search for mythical medicinal herb—Sanjeevani Booti. India Times, 29 July. Available at: https://www.indiatimes.com/news/india/uttarakhand-government-
12 Pandey JM (2017) IIT Kharagpur to introduce Vastu
13 Shastra. *The Times of India*, 17 April. Available at: https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/iit-kharagpur-to-introduce-vastu-shastra/articleshow/58213293.cms
14 शायरा बानो बनाम भारत संघ केस–सुप्रीम कोर्ट WP(C) 118/2016